संशोधन लाया गया था, उस समय डीएमएफ बनाया था। माननीय पीयूष गोयल जी यहां बैठे हुए हैं। उस डीएमएफ के माध्यम से यह काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरा, सबको स्वच्छ पेयजल मिले, यह बहुत जरूरी है। हमारे देश में अनेक स्थान ऐसे हैं, लगभग 66,663 ऐसी बसावटें हैं, जहां पेयजल की गुणवत्ता खराब है। सरकार की कोशिश है कि चाहे वह आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वह फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वह नाइट्रेट प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वह लौह प्रभावित क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में जल शुद्ध हो सके और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है और वित्तीय सहायता राज्यों को दे रही है। पिछली बार भी, जब सरकार के पास बजट की कमी थी, तब नीति आयोग ने 800 करोड़ रुपया जल गुणवत्ता के लिए दिया था। पश्चिमी बंगाल और राजस्थान दोनों राज्यों के जो ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए 100-100 करोड़ रुपया अलग से दिया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जल गुणवत्ता उपमिशन भारत सरकार ने प्रारम्भ किया है। इस बार इसको बजट में भी अनाउंस किया गया है। इसके माध्यम से काम प्रारम्भ हो गया है। हम लोग आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित जो क्षेत्र हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी बंगाल और राजस्थान है, बाकी अन्य राज्यों में छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, जहां पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है और जल की गुणवत्ता नहीं होती है। हम वहां पर जल गुणवत्ता उपमिशन प्रारम्भ कर रहे हैं। यह पूरी 25,000 करोड़ रुपये की परियोजना है। केंद्रांश साढ़े बारह करोड़ रुपया है, 760 करोड़ रुपया इस बार राज्य सरकारों को रिलीज़ कर दिया गया है। इनके माध्यम से परियोजनाएं चल रही हैं और आने वाले कल में यह सुनिश्चित हो सकेगा कि स्वच्छ पेयजल लोगों को मिले।

श्री संजय सेठः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए साफ पानी देने के लिए आर0ओ0 सिस्टम कई राज्यों में लगाए गए हैं। क्या आर.ओ. सिस्टम लगाने का काम केंद्र सरकार की किसी योजना के अंतर्गत है और इसको लगाने में कितना खर्च आ रहा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आर0ओ0 सिस्टम कहां-कहां पर लगे हुए हैं?

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः सभापति महोदय, मैं जो जवाब दे रहा हूं, वह ग्रामीण क्षेत्र का ही है। ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, उसके लिए छोटे-छोटे सुधार करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में, अनेक राज्यों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार 9,113 जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए हैं और उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। अभी राजस्थान ने एक "जलमणि" परियोजना शुरू की, जिसके माध्यम से लगभग एक लाख स्कूलों में इस प्रकार की परियोजना को पूर्णता प्रदान की है। वहां पर एक हजार लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रति-दिन लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की उस आर.ओ. परियोजना में लागत आती है।

*34. [**प्रश्नकर्ता अनुपस्थिति थे।**]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों का मानव विकास सूचकांक

*34. **श्री पी. एल. पुनियाः** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के मानव विकास सूचकांक की तुलना में अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति वर्गों का मानव विकास सूचकांक कम है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जाति और अनूसचित जनजाति वर्ग मानव विकास सूचकांक के किन-किन सूचकों में पीछे है; तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) गरीबी अनुपात, साक्षरता दर, स्कूल डॉपआउट दर, विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों, आदि के संबंध में अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा अन्य सामाजिक समूहों के मानव विकास सूचकांकों की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा अनुबंध में संबंधित तालिकाओं में दिया गया (**नीचे देखिए**) है। अनुबंध में दिया गया डाटा यह दर्शाता है कि विगत वर्षों में अ.जा. और अ.ज.जा. के मानव विकास सूचकांकों में सुधार हुआ है, हालांकि, इनके तथा अन्य सामाजिक समूहों के बीच सूचकांकों में अंतर अभी भी विद्यमान है। इस अंतर के मुख्य कारण गरीबी और इसका दुष्चक्र, निरक्षरता, मुख्यतया मजदूरी श्रम पर निर्भरता, आदि हैं और सरकार विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इनका समाधान कर रही है।

(ग) अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों में मानव विकास सूचकांक में अंतर को कम करना सामाजिक आर्थिक विकास नीति की हमेशा प्राथमिकता रही है और सरकार इसके प्रति बचनबद्ध है। इसके लिए पहले ही से कई कार्यक्रम प्रचालन में हैं और इनका उद्देश्य सघन अनुवीक्षण और पारदर्शिता के माध्यम से कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है ताकि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, उद्यमिता और अवसंरचना विकास कार्यक्रमों के माध्यम से तथा संबंधित कार्यक्रमों के तहत निधियों के आबंटन को बढ़ाकर अ.जा. और अ.ज.जा. के समग्र मानव विकास सूचकांकों को सुधारने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए जा रहे हैं। अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए अनन्य रूप से प्रमुख सतत् कार्यक्रम भी हैं जिन्हें क्रमशः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने भी "अ.जा. और अ.ज.जा. के कल्याण हेतु आबंटन" उद्दिष्ट किए हैं जिनका ब्यौरा संघीय व्यय बजट 2017-18 में अजा के लिए विवरण 10क में और अ.ज.जा. के लिए 10ख में उपलब्ध है। "अ.जा. के कल्याण हेतु आबंटन" समग्र रूप 2016-17 में 38833 करोड़ रूपये (ब.अ.) से बढ़कर 2017-18 में 52393 करोड़ रूपये (ब.अ.) हो गया है अर्थात् इसमें 35% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, अ.ज.जा. के कल्याण के लिए कुल आबंटन 2016-17 में 24005 करोड़ रूपये (ब.अ.) से बढ़कर 2017-18 में 31920 करोड़ रूपये (ब.अ.) हो गया है अर्थात् इसमें 33% की वृद्धि हुई है। 2016-17 तक, अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए उद्दिष्ट की गई स्कीम-वार/मंत्रालय-वार निधियों का ब्यौरा व्यय बजट खंड-I के विवरण 21 और 21-क में क्रमशः अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत दर्शाया जाता था।

सरकार ने 2016-17 में एक अन्य महत्वपूर्ण नई पहल के तौर पर स्टैंड-अप इंडिया स्कीम शुरू की है जिसके अंतर्गत हरित क्षेत्र उद्यम (विनिर्माण, सेवाएं अथवा व्यापार क्षेत्र) स्थापित करने के लिए, प्रति बैंक शाखा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कम-से-कम एक व्यक्ति को 10 लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक का बैंक ऋण दिया जाता है।

अनुबंध

गरीबी अनुपात, साक्षरता दर, स्कूल डॉपआउट दर, विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों, आदि के संबंध में अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) तथा अन्य सामाजिक समूहों के मानव विकास सूचकांकों की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा

तालिका-1 विभिन्न सामाजिक समूहों में गरीबी की व्यापकता

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी		
	2004-05	2009-10	2011-12	2004-05	2009-10	2011-12
अनुसूचित जातियां	53.53	42.26	31.50	40.56	34.11	21.70
अनुसूचित जनजातियां	62.28	47.37	45.30	35.52	30.38	24.10
कुल	41.79	33.80	25.40	25.68	20.09	13.70

स्रोतः योजना आयोग।

तालिका-2 सामाजिक समूहों के लिए स्वास्थ्य संकेतक

वर्ष	एनएफएचएस-1 (1992-93)			एनएफएचएस-2 (1998-99)			एनएफएचएस-3 (2005-06)		
मुख्य संकेतक/सामाजिक समूह	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
शिशु मृत्यु दर	107.0	90.5	86.3	83.0	84.2	73.0	66.4	62.1	57.0
नवजात मृत्यु दर	63.1	54.6	52.7	53.2	53.3	47.7	46.3	39.9	39.0
बाल मृत्यु दर	46.9	49.1	35.5	39.5	46.3	30.6	23.2	35.8	18.4
पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर	149.0	135.2	118.8	119.3	126.6	101.4	88.1	95.7	74.3

स्रोतः 1992-93 से 2005-06 तक का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण।

तालिका-3 सामाजिक समूहों की साक्षरता दर

सामाजिक समूह	1981	1991	2001	2011
अनुसूचित जातियां	21.38	37.41	54.69	66.07
अनुसूचित जनजातियां	16.35	29.60	47.10	58.96
कुल	43.57	52.21	64.84	74.00

स्रोतः जनगणना डेटा।

तालिका-4 अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक समूहों के लिए स्कूल ड्रॉपआउड दर (कक्षा IX-X)

	कक्षा	1990-91	2000-01	2009-10	2013-14
अनुसूचित जाति	I-V	49.4	45.2	29.3	16.6
	I-VIII	67.8	63.6	52	38.8
	I-X	85	72.7	59	50.1
अनुसूचित जनजाति	I-V	62.5	52.3	34.5	31.3
	I-VIII	78.6	68.7	57.8	48.2
	I-X	85	81.2	75.2	62.4
कुल	I-V	42.6	40.7	30.3	19.8
	I-VIII	60.9	53.7	42.5	36.3
	I-X	71.3	68.6	52.7	47.4

स्रोतः शैक्षिक आंकड़े एक नजर में, 2014 मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

तालिका-5 वार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (यूईएस) के अनुसार 15 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर)

(प्रतिशत में)

सामाजिक समूह	दूसरा ईयूएस (जुलाई-2011)	तीसरा ईयूएस (अक्टूबर-2012)	चौथा ईयूएस (दिसंबर-2013)	पांचवां ईयूएस (अगस्त-2016)
अनूसूचित जाति	3.2	4.5	4.6	5.0
अनूसूचित जनजाति	2.6	3.6	4.5	4.4
कुल	3.8	4.7	4.9	5.0

स्रोतः श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय (सामान्य प्रधान स्थिति यूपीएस दृष्टिकोण)।

*34. **[The questioner was absent.]**

Human Development Index of SCs and STs

†*34. SHRI P. L. PUNIA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Human Development Index of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) is less as compared to that of the country, if so, the details thereof;

(b) the details of indicators wherein SCs and STs lag behind in Human Development Index alongwith the reasons therefor; and

† Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether Government proposes to formulate any special action plan to enhance the Human Development Index of SCs and STs, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING (RAO INDERJIT SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The details of comparative picture of Human Development Indices (HDIs) of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and other Social Groups with respect to poverty ratio, literacy rate, school dropout rate, various health indicators, etc. are given in respective tables in Annexure (*See* below). The data in the Annexure show that there has been improvement in the Human Development Indices of SCs and STs over the years, even if the gap in the indices remains between them and other social groups. The main reasons for the gap are poverty, and its vicious circle, illiteracy, dependence largely on wage labour etc., which the Government has been addressing through various socio-economic development programmes.

(c) Reduction of gap in the HDIs amongst SCs, STs and other social groups has always been the priority of socio-economic development policy and Government is committed to it. A large number of programmes are already in operation and the aim is to improve implementation through close monitoring and transparency so that desired objectives are achieved.

There are major on-going programmes exclusively for SCs and STs implemented respectively by the Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs. The concerned Central Ministries and Departments also have earmarked "Allocations for the welfare of SCs and STs", details of which are available in Statement 10-A for SCs and 10-B for STs in the Union Expenditure Budget 2017-18. The total "Allocation for the welfare of SCs" has increased from ₹ 38833 crore (BE) in 2016-17 to ₹ 52393 crore (BE) in 2017-18 *i.e.* an increase of 35%. Similarly, the total allocation for the welfare of STs has increased from ₹ 24005 (BE) crore in 2016-17 to ₹ 31920 crore (BE) 2017-18 *i.e.* an increase of 33%. Up to 2016-17 Scheme-wise/Ministry-wise funds earmarked for SCs and STs were shown in Statement 21 and 21-A of the Expenditure Budget Volume-I under Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP) and Tribal Sub-Plan (TSP) respectively.

An important new initiative taken by the Government is launching of Stand-Up India Scheme, in 2016-17 under which bank loans between ₹ 10 lakh to ₹ 1 crore is given to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower, per bank branch, for setting up a Greenfield enterprise (manufacturing, services or the trading sector).

Annexure

Details of comparative picture of Human Development Indices (HDIs) of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and other Social Groups with respect to poverty ratio, literacy rate, school dropout rate and various health indicators, etc.

Table-1: Incidence of Poverty across Social Groups

Social Groups	Rural			Urban		
	2004-05	2009-10	2011-12	2004-05	2009-10	2011-12
SCs	53.53	42.26	31.50	40.56	34.11	21.70
STs	62.28	47.37	45.30	35.52	30.38	24.10
TOTAL	41.79	33.80	25.40	25.68	20.09	13.70

Source: Planning Commission.

Table-2: Health Indicators for social groups

Year	NFHS-1 (1992-93)			NFHS-2 (1998-99)			NFHS-3 (2005-06)		
Key Indicators/Social groups	SCs	STs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs	Total
Infant Mortality	107.0	90.5	86.3	83.0	84.2	73.0	66.4	62.1	57.0
Neo-Natal Mortality	63.1	54.6	52.7	53.2	53.3	47.7	46.3	39.9	39.0
Child Mortality	46.9	49.1	35.5	39.5	46.3	30.6	23.2	35.8	18.4
Under Five Mortality	149.0	135.2	118.8	119.3	126.6	101.4	88.1	95.7	74.3

Source: National Family Health Survey, from 1992-93 to 2005-06.

Table-3: Literacy rate of Social Groups

Social Groups	1981	1991	2001	2011
SCs	21.38	37.41	54.69	66.07
STs	16.35	29.60	47.10	58.96
TOTAL	43.57	52.21	64.84	74.00

Source: Census data.

Table-4: School Dropout Rate for Social Groups on All India (Class-IX-X)

	Classes	1990-91	2000-01	2009-10	2013-14
SCs	I-V	49.4	45.2	29.3	16.6
	I-VIII	67.8	63.6	52	38.8
	I-X	85	72.7	59	50.1
STs	I-V	62.5	52.3	34.5	31.3
	I-VIII	78.6	68.7	57.8	48.2
	I-X	85	81.2	75.2	62.4
TOTAL	I-V	42.6	40.7	30.3	19.8
	I-VIII	60.9	53.7	42.5	36.3
	I-X	71.3	68.6	52.7	47.4

Source: Educational Statistics at Glance 2014, MHRD.

Table-5: Unemployment Rate (UR) of persons aged 15 years and above according to Annual Employment and Unemployment Survey (UES)

(in percent)

Social Groups	2nd EUS (July, 2011)	3rd EUS (October. 2012)	4th EUS (December, 2013)	5th EUS (August, 2016)
SCs	3.2	4.5	4.6	5.0
STs	2.6	3.6	4.5	4.4
TOTAL	3.8	4.7	4.9	5.0

Source: Labour Bureau, M/o Labour and Employment (Usual Principal Status UPS approach).

MR. CHAIRMAN: Question No. 34. Shri Punia; not present. Are there any supplementaries?

DR. NARENDRA JADHAV: Mr. Chairman, Sir, I have a comment and a supplementary question.

MR. CHAIRMAN: Question only please.

DR. NARENDRA JADHAV: Okay, Sir. My supplementary question is: Is it not true that funds amounting to ₹ 12,000 crores meant for post-matric scholarships for *Dalits* and *Adivasis* were not spent last three years? This is a very serious situation, Sir. If it is true, I would like to know from the Hon. Minister why this amount of money was not spent. Thank you.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, it is a specific question which does not have relevance to this one, I will let the Member know later on.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Husain Dalwai.

श्री हुसैन दलवईः सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वहां पर एससी और एसटी के लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, माइनॉरिटी के लोगों को पहले जो स्कॉलरशिप्स यूपीए के ज़माने में दी जाती थीं, उनमें से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स बंद कर दी गई हैं। इसके बारे में पूछा गया है, तो आपके द्वारा उत्तर न देना गलत है। उसके बारे में आपका क्या कहना है, वह तो हम सुनें।

राव इंद्रजीत सिंहः सर, स्कॉलरशिप महाराष्ट्र का सवाल नहीं है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के Human Development Indices के अंदर वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, उसका सारा ब्यौरा मैंने लिखकर दे दिया है। और कुल मिलाकर हमने पिछले साल के बनिस्बत इसे हर साल बढ़ाया है। सर, अब एक स्टेट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार जवाबदेह नहीं है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, how can the hon. Minister answer like this? HDI is dependent on education; education is dependent on scholarships. And he is saying that it does not apply to this question. This is a most irresponsible way of answering a question, Sir.

MR. CHAIRMAN: You made your point.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, there are various schemes under which the Government of India empowers State Governments. Over hundred heads Departments that are there, there has been an increase of 35 per cent for Scheduled Castes and there has been a 33 per cent increase for Scheduled Tribes over the previous Budget Estimates. Now, these Schemes are not implemented directly by the Central Government. It is left to the State Government to implement them. So, there has been a provision in all Departments of the Central Government, and I can say for the Budget Estimates, 2017-18, say in a Department like Agriculture, in the actuals of 2015-16, it was ₹ 1,463 crores for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In the Budget Estimates, 2017-18, it has increased to ₹ 6,668 crores. Like that, there are hundred heads/Departments. In every Department, there has been an increase. Each Department passes on its schemes to the State Governments concerned and the State Governments are the implementing agencies.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, the reply of the Union Minister has rightly established the fact that during the UPA's ten-year period, the interventions by the UPA Government has enabled to reduce the school dropout levels among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to a great extent.

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Yes, coming to that, Sir. For Scheduled Castes, it was earlier, when we, the UPA, assumed office, at 72 per cent wherein that has reduced to 50 per cent, and in the case of Scheduled Tribes, which was at 81 per cent, it has reduced to 62 per cent.

MR. CHAIRMAN: You are not asking a question.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: In the same manner, the unemployment rate has been greatly addressed by the UPA policies.

MR. CHAIRMAN: No, no, you are not asking a question. ...(*Interruptions*)... Look, please ask the question or I go on to the next one. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Mr. Chairman, Sir, why by August, 2016 the unemployment rate has increased from 4.6 to 5 among the Scheduled Castes? Have you studied it? Since this question pertains to the Human Development and Human Poverty Indices which are greatly impacting the living standards of those communities, I would like to know whether the Union Ministry has studied why there is a jump in the unemployment rate among the Scheduled Castes. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: I think questions can be asked without an *aalaap* period. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, at times, it is required. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, the unemployment rate, I think this is what the question is all about, the Scheduled Tribes' unemployment rate in 2011 July was 2.6. It has increased, as have the other indices, to 4.4 in August, 2016. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... No, no, Mr. Rapolu. Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Let the hon. Minister answer. ...(*Interruptions*)... Please.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, as I have understood, he is asking about the unemployment rate. If he had been more specific, I would have answered more specifically. He rambled around everything and then hasn't asked a question. So, what I have been able to understand, I am trying to answer. You can ask a supplementary, if you are not satisfied. But what I have understood so far, Mr. Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let us not get into a controversy. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Will you please sit down?

RAO INDERJIT SINGH: Sir, I would just like to let the hon. Member as well as the House know that the unemployment rate for the Scheduled Castes in 2011 was 3.2 per cent. Today it has gone to 5 per cent. For STs, it was 2.6 per cent and it has gone to 4.4 per cent. Total unemployment rate in the country has also gone up. It was 3.8 per cent in July, 2011, and has become 5 per cent today. As far as reserved categories are concerned, the highest incidence of unemployment today is of OBCs. It was 3.2 per cent in 2011 and has become 5.2 per cent in August, 2016.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I would like to know whether statistics that the hon. Minister has read out now indicate increase in employment or increase in unemployment.

MR. CHAIRMAN: The answer is about unemployment.

Making Aadhaar cards mandatory under MGNREGS

*35. SHRI D. RAJA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government is considering a proposal to make Aadhaar cards mandatory for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAM KRIPAL YADAV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government in the Ministry of Rural Development has notified on 3rd January, 2017 that any individuals registered under the Mahatma Gandhi NREGA who is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, and in case, she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre to get enrolled for Aadhaar. Till the time Aadhaar is assigned to the individual, she or he shall be allowed to work under the Mahatma Gandhi NREG